रिविजनल सिविल

माननीय न्यायाधीश हरबंस लाल के समक्ष

गेला रैम आदि, *याचिकाकर्ता*

बनाम

कैलाश नाथ और अन्य, उत्तरदाता

सिविल संशोधन सं. 1975 *का* 826

22 दिसंबर, 1975

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का वी) - आदेश 6 नियम 17 - कई विक्रेताओं के पक्ष में संपत्ति की बिक्री - एक पूर्व-विवाद वाद में शामिल नहीं किया गया है - इस तरह के प्रतिशोध को सीमा की अवधि के बाद वाद में संशोधन द्वारा पक्षकार बनाया जाना चाहिए - संशोधन - क्या अनुमति दी जानी चाहिए।

अभिनिर्धारित किया, कि पूर्व-अनुभव का अधिकार एक पितृसत्तात्मक अधिकार है और इक्विटी प्रतिशोध के पक्ष में है। यदि वादी इस तरह के अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी स्तर पर दोषी पाया जाता है, तो वह संशोधन या अन्यथा के मामले में किसी भी उदारता का हकदार नहीं है। इसलिए यदि किसी पूर्व-साक्षात्कार मुकदमे में वादी कई अभियोगियों में से किसी एक को पक्षकार नहीं बनाता है और बाद में सीमा की अवधि के बाद वाद में संशोधन करके उसे पक्षकार बनाने का प्रयास करता है, तो संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (पैरा 2)।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत श्री केके डोडा, उप-न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, फतेहाबाद के दिनांक 22 मार्च, *1975 के आदेश में संशोधन के लिए याचिका दायर की गई है, जिसमें* वाद में संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति दी गई है, लेकिन 10,000/- रुपये के भुगतान के अध्यधीन। लागत के रूप में 30 रुपये /

याचिकाकर्ता की ओर से राम रंग, वकील, 1

प्रतिवादी संख्या 10 की ओर *से एएस नेहरा, एडवोकेट।* 1

जी. एस. चावला, अधिवक्ता, प्रतिवादी *संख्या 100 के लिए।* ।

निर्णय

माननीय न्यायाधीश हरबंस लाल

(1) यह पुनरीक्षण याचिका अधीनस्थ न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी, फतेहाबाद के आदेश के विरुद्ध निर्देशित की जाती है, जिसमें वाद-पत्र में संशोधन की अनुमति दी गई है। प्रतिवादी कैलाश नाथ ने गेला राम, हरबंस लाई, राम दास और राम किशन के पक्ष में अपने पिता द्वारा मुकदमा संपत्ति की बिक्री को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया। इन चार लोगों के अलावा अमर दित्ता भी खरीदारों में से एक था, लेकिन उसे पहली बार में वाद पत्र में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था। 10 अप्रैल, 1973 के बिक्री

विलेख के अनुसार, विवादित भूमि का एक आधा हिस्सा गेला राम और हरबंस लाल के पक्ष में बेचा गया था और शेष आधा राम किनेन, राम दास और अमर दत्ता के पक्ष में बेचा गया था। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मूल मुकदमा अमर दत्ता, वेंडी नाम को छोड़कर चार वेंडी के खिलाफ दायर किया गया था। यह बिक्री 10 अप्रैल, 1973 की है। यह मुकदमा 27 फरवरी, 1974 को दायर किया गया था। 13 दिसंबर, 1974 को दायर अपने लिखित बयान में प्रतिवादियों ने एक विशिष्ट आपत्ति जताई कि सभी प्रतिवादियों को पक्षकार नहीं बनाया गया था और इसलिए, मुकदमे को आंशिक पूर्व-अनुभव के मामले के रूप में खारिज किए जाने की संभावना थी। वादी-प्रतिवादी कमलेश नाथ ने 26 दिसंबर, 1974 को वाद में संशोधन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम 17 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें शेष प्रतिवादी अमर दत्ता को प्रतिवादियों में से एक के रूप में शामिल करने की अनुमति मांगी गई। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को अनुमति दी और निम्नानुसार देखा:

> "मैं वादी के वकील से सहमत हूं कि वादी ने नेक नीयत से काम किया। वादी द्वारा की गई गलती निश्चित रूप से प्रामाणिक है /उन्होंने वाद-पत्र में उन लोगों के नामों का उल्लेख किया, जो वाद-पत्र के साथ विक्रय विलेख की प्रति में दिए गए थे। उसे उप-रजिस्ट्रार की नकल एजेंसी या वाद का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति द्वारा की गई गलती के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है।

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री राम रंग ने जोरदार आग्रह किया है कि यह गलत है कि वादी-प्रतिवादी, कैलाश नाथ ने प्रतिवादी के रूप में एक प्रतिवादी को पक्षकार नहीं बनाकर एक वास्तविक गलती की। उनके अनुसार, बिक्री विलेख की प्रति में हालांकि अमर दत्ता का नाम विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक आधी जमीन राम किशन और राम दास को बेची गई थी और सभी "तीनों" समान शेयरों में भूमि के हकदार होंगे। बिक्री विलेख की प्रति का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने से वादी-प्रतिवादी, कैलाश नाथ को यह पूछने पर रखा जाना चाहिए था कि "तीन" शब्द का उल्लेख कैसे और क्यों किया गया था (जिसका अर्थ है कि तीन खरीदार थे और एक आधी जमीन में से दो नहीं) और उन्हें (वादी-प्रतिवादी कैलाश नाथ) सभी नामों का पता लगाने के लिए उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाना चाहिए था। आगे आग्रह किया गया है कि वाद पत्र के साथ संलग्न *जमाबंदी* की प्रति से यह स्पष्ट है कि बिक्री के संबंध में एक उत्परिवर्तन को भी मंजूरी दी गई थी और वादी-प्रतिवादी, कैलाश नाथ, पटवारी से म्यूटेशन और अन्य प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड से वेनियों के नामों को बहुत अच्छी तरह से सत्यापित कर सकते थे। इस संबंध में रिलायंस को *ज्वाला दास और अन्य पर रखा गया* है। *गोपाल लाई और देस राज और अन्य,* (1). *जावला दास के मामले* (सुप्रा) में भी एक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने वादी को निर्देश दिया कि वह उस व्यक्ति को आरोपी बनाए, जिसे प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन चूंकि उसे सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी बनाया गया था, इसलिए मुकदमा खारिज कर दिया गया था। अपील में, जिला न्यायाधीश ने कहा कि पंजीकरण विभाग द्वारा वादी को प्रदान की गई बिक्री विलेख की गलत प्रति के कारण एक प्रतिवादी को शामिल करने में चूक हुई। नतीजतन, यह माना गया कि हालांकि संशोधन के समय मुकदमे को समय से रोक दिया गया था, लेकिन मुकदमे में प्रतिवादियों का केवल गलत वर्णन किया गया था। दूसरी अपील में, निचली अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया गया था और इसे निम्नानुसार माना गया था:

> "पार्टियों का केवल गलत विवरण नहीं था, और बी को सीमा की समाप्ति के बाद शामिल नहीं किया जा सकता था और परिणामस्वरूप, पूरा मुकदमा विफल हो जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने शंकर सिंह बनाम भारत से भी समर्थन प्राप्त किया है। *चानन सिंह,* (2) *गुरमुख सिंह* वी। *दलीप सिंह और अन्य,* (3) *श्रीमती गुरदीप कौर* बनाम *केहर सिंह और एक अन्य,* (4), *और बंता सिंह और अन्य* वी। *श्रीमती हरभजन कौर और अन्य,* (5)। इन सभी मामलों में, पूर्व-अनुभव

के लिए वाद में वाद के संशोधन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि सीमा की अवधि की समाप्ति के परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों में मूल्यवान अधिकार निहित थे। दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने *दीदार सिंह और अन्य पर भरोसा किया* है। *दलबीर सिंह और एक अन्य, (6),* बंता सिंह और एक अन्य *वी। श्रीमती हरभजन कौर और अन्य,* (7) *और जलाल दीन और अन्य कैम दीन और मुसम्मत एक्सजेमार बीबी और अन्य* (8)। *दीदार सिंह के मामले* (सुप्रा) तुली में, जे. (जैसा कि वह तब थे) इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गलती वाद पत्र के ड्राफ्ट्समैन द्वारा की गई थी, जिसने संभवतः बिक्री विलेख के पहले भाग से बेची गई संपत्ति के विवरण का उल्लेख किया था, जहां आमतौर पर इसका उल्लेख किया जाता है और यह नहीं देखा गया था कि बेची गई संपत्ति के किसी भी हिस्से का उल्लेख बिक्री विलेख के अंत में भी किया जा सकता है। इसे देखते हुए संशोधन की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया था।

श्रीमती हरभजन कौर के मामले (सुप्रा) में उस संपत्ति के विवरण में गलती अनजाने में हो गई थी, जिससे बिक्री संबंधित थी और गुरदेव सिंह, जे (जैसा कि वह तब थे) ने संशोधन की अनुमति देते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि वाद में संशोधन करके कोई नया दावा या नया मामला पेश नहीं किया गया था। इसी तरह *जलाल दीन के मामले* (सुप्रा), जो अनजाने में संपत्ति के गलत विवरण का मामला था, में इसे निम्नानुसार माना गया था:

> "यह दावा की गई संपत्ति के असावधानी और गलत विवरण का मामला था, न कि जानबूझकर चूक का और संशोधन तदनुसार स्वीकार्य थे।

रिलायंस को जय जय राम मनोहर लाई *वी पर भी रखा गया* है। *राष्ट्रीय भवन निर्माण सामग्री आपूर्ति, गुड़गांव,* (9). *जय जय राम मनोहर लाई का मामला* (सुप्रा) भी वादी द्वारा फर्म के नाम के गलत वर्णन का मामला था। उस मामले में, यह सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्ड-जहाजों द्वारा निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

> "एक ऐसे मामले में एक फर्म नाम द्वारा वादी का विवरण जहां सिविल प्रक्रिया संहिता फर्म नाम में मुकदमा लाने की अनुमति नहीं देती है, को ठीक से व्यवसाय के व्यक्तिगत भागीदारों के विवरण के मामले के रूप में माना जाना चाहिए और इस तरह के गलत विवरण के रूप में, जिसे कानून में ठीक किया जा सकता है। इसे गैर-मौजूद व्यक्ति के वर्णन के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।

ऊपर उल्लिखित निर्णयों के गहन अवलोकन से यह स्पष्ट है कि केवल उन मामलों में जहां विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे, कि यह केवल उन मामलों में है जहां पूर्व मूल्यांकन मामलों में संपत्ति या पार्टियों के गलत विवरण का मामला था कि संशोधन की अनुमति दी गई थी और निष्कर्ष निकाला गया था कि इस तरह का गलत विवरण प्रामाणिक था / और जैसे! असावधानी का परिणाम। बार में किसी भी मामले का हवाला नहीं दिया गया है, जहां *जावला दास के* मामले (सुप्रा) में लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लिया गया हो, जिसके तथ्य लगभग मामले के समान हैं। मेरे ध्यान में ऐसा कोई निर्णय नहीं लाया गया है जिसमें वाद में संशोधन की अनुमति दी गई हो ताकि किसी ऐसे पक्ष का नाम शामिल किया जा सके जिसे सीमा की समाप्ति के बाद प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी के रूप में अमर दत्ता का नाम शामिल करने से चूक को नेकनीयती का कार्य भी नहीं माना जा सकता है। परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 2 (एच) में "सद्भावना" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जो अच्छे विश्वास के साथ किया गया है जो उचित देखभाल और ध्यान के साथ नहीं किया जाता है।

यदि वादी-प्रतिवादी, कैलाश नाथ ने "उचित देखभाल और ध्यान" का उपयोग किया था, तो उन्हें जांच पर रखा जाना चाहिए था कि सभी खरीदारों, अर्थात् राम किशन और राम दास के नामों का उल्लेख करने के बाद, "तीन" शब्द (जिसका अर्थ है तीन खरीदार) का उल्लेख क्यों किया गया था और उन्होंने आसानी से उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय से या पटवारी के कब्जे में राजस्व रिकॉर्ड से तीन वेंडी के नाम का पता लगा लिया होगा। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने अपने लिखित बयान में 13 दिसंबर, 1974 को एक विशिष्ट आपत्ति ली थी, लेकिन प्रतिवादी ने बारह दिनों तक वाद में संशोधन के लिए आवेदन दायर नहीं किया और 26 दिसंबर, 1974 को ही आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इससे स्पष्ट है कि वादी-प्रतिवादी कैलाश नाथ अपने मामले पर उचित ध्यान नहीं दे रहे थे। इस मामले के इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि वादी-प्रतिवादी, कैलाश नाथ की ओर से वाद-पत्र में एक प्रतिवादी अमर दत्ता को पक्षकार बनाने में चूक केवल असावधानी का कार्य नहीं था और ट्रायल कोर्ट ने वाद के संशोधन की अनुमति देने में अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके अवैधता की थी। कानून दृढ़ता से स्थापित है कि पूर्व-अनुभव का अधिकार एक पितृसत्तात्मक अधिकार है और इक्विटी प्रतिशोध के पक्ष में है। यदि वादी इस तरह के अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी स्तर पर दोषी पाया जाता है, तो वह संशोधन या अन्यथा के मामले में किसी भी उदारता का हकदार नहीं है।

(3) उपर्युक्त कारणों से, यह संशोधन याचिका सफल होती है और इसे लागत के साथ स्वीकार किया जाता है। निचली अदालत के 22 मार्च, 1975 के आदेश को निरस्त किया जाता है और वादी प्रतिवादी कैलाश नाथ का सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश छह नियम 17 के तहत वाद में संशोधन के आवेदन को खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वीरेंद्र कुमार
प्रीक्षिशु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़